

प्रेषक,

नितेश कुमार झा,  
अपर सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,  
उच्च शिक्षा,  
हल्द्वानी, नैनीताल।

शिक्षा अनुभाग-7 (उच्च शिक्षा)

देहरादून दिनांक 08 / सितम्बर 2010

विषय:- वित्तीय वर्ष 2010-2011 में राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बागेश्वर विशिष्ट महाविद्यालय योजनान्तर्गत भवन निर्माण हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या डिग्री विकास/4552/2010-11 दिनांक 22-4-2010 तथा शासनादेश संख्या 917/xxiv (7)/2006 दिनांक 18-1-07, शासनादेश संख्या 76/xxiv (7) 82(2)/2008 दिनांक 17-11-08 एवं शासनादेश संख्या 498/xxiv(7)82(2)/2008 दिनांक 12-3-2010 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय राजकीय महाविद्यालय बागेश्वर को विशिष्ट महाविद्यालय के रूप में विकसित करने के लिये भवन निर्माण हेतु उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम के अनुमोदित आगणन रु0 287.58 लाख के विरुद्ध अवशेष धनराशि रु0 147.58 लाख के सापेक्ष वर्तमान वित्तीय वर्ष 2010-11 में रु0 25.00 लाख (रु0 पच्चीस लाख मात्र) को व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. स्वीकृत धनराशि को उपरोक्त कार्य के अतिरिक्त किसी अन्य कार्य में व्यय नहीं किया जायेगा तथा अतिरिक्त धनराशि की स्वीकृति की प्रत्याशा में कोई अन्य व्यय नहीं किया जायेगा एवं समय-समय पर निर्गत वित्तीय एवं मित्तव्ययता सम्बन्धी नियमों एवं दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का आहरण निदेशक, उच्च शिक्षा द्वारा करने के उपरान्त सम्बन्धित निर्माण इकाई को अवमुक्त किया जायेगा। यह भी सुनिश्चित किया जाय कि धनराशि अनावश्यक रूप से बैंकों में पार्किंग के रूप में न रखी जाय।

3. स्वीकृत धनराशि के उपयोग के सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत समस्त शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा निर्माण कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से शासन को अवगत कराया जायेगा। निर्माण कार्य के लिये अवमुक्त की गई धनराशि का उपभोग तथा कार्य पूर्ण किया जाना शीघ्रता से इसी वित्तीय वर्ष में करने के लिये प्राचार्य द्वारा समुचित पर्यवेक्षण किया जायेगा तथा निर्माण इकाई द्वारा विलम्ब करने की दशा में शासन द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जावेगी। विलम्ब की दशा में आगणन पुनरीक्षण पर विचार नहीं किया जायेगा।

4- निदेशक उच्च शिक्षा कार्यदाई संस्था को धनराशि अवमुक्त करने से पूर्व कार्यदाई संस्था से एक सप्ताह में अवमुक्त की जाने वाली धनराशि के विरुद्ध एकेडिमिक रिक्वायरमेंट के अनुरूप समय सारणी अनुसार कार्य पूर्ण करने की लिखित सहमति प्राप्त कर लेंगे। यदि लिखित समयावधि के अन्तर्गत कार्य पूर्ण नहीं किया जाता है तो, एक माह का ग्रेस पीरियड देते हुये कार्यदाई संस्था से 5 प्रतिशत आर्थिक

जुर्माना वसूला जायेगा। तीन माह से अधिक विलम्ब होने पर कार्यदाई संस्था को काली सूची में सम्मिलित करने हेतु कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

5- तृतीय पक्ष गुणवत्ता (Third party quality) सुपरविजन तथा अनुश्रवण के सम्बन्ध में सी0बी0आर0आई0 रुडकी की संस्तुति के आधार पर पुराने निर्माण कार्यों का तृतीय पक्ष सुपरविजन एवं गुणवत्ता का परीक्षण किया जाना सम्भव नहीं है। अतः किये गये निर्माण कार्य की गुणवत्ता का निरीक्षण सम्बन्धित महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सुनिश्चित कर लिया जाय।

6- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2010-11 के आय-व्ययक की अनुदान सं0 11 के आयोजनागत पक्ष के अधीन लेखा शीर्षक-4202-शिक्षा खेल कूद तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय -01- सामान्य शिक्षा-203-विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा- आयोजनागत- 11-आदर्श महाविद्यालयों की स्थापना -24-बृहत्त निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

7- यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 249/xxxvii(1)/2010 दिनांक 4-5-2010 में निर्गत दिशा निर्देशों के अनुरूप निर्गत किये जा रहें हैं।

भवदीय,

(नितेश कुमार झा)

अपर सचिव

सं0 1497(1)/ xxiv (7)82(2)/2008 तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- आयुक्त कुमाऊँ मण्डल।
- 3- जिलाधिकारी बागेश्वर।
- 4- कोषाधिकारी हल्द्वानी-नैनीताल।
- 5- अधिशासी अभियंता, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, बागेश्वर।
- 6- प्राचार्य, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बागेश्वर।
- 7- निदेशक एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड।
- 8- बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन सचिवालय देहरादून।
- 9- वित्त अनु0-3/नियोजन प्रकोष्ठ उत्तराखण्ड शासन।
- 10- विभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(पी0 एल0 शाह)

उप सचिव